Private Sector Assistance in the NCR

1450. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have sought assistance from the private sector to develop requisite facilities for the people of National Capital Region (NCR);

(b) if so, the details of help sought from the private sector; and

(c) the response of the private sector to the invitation extended by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) It has been estimated that in order to implement the various development programmes in the National Capital Region, a total investment of about Rs. 59,000 crores would be required upto the year 2005. The larger part of this requirement is envisaged to flow from the private sector largely for the creation of economic infrastructure of industries, trade and commerce for generating the requisite level of employment opportunities in the Region and provide shelter through development of housing and other social infrastructure.

The NCR Planning Board has been regularly liaising with the apex bodies of the private sector such as the Chambers of Commerce, Builders' Association etc. in an effort to evolve appropriate steps to facilitate their active participation in the development programmes in the NCR.

सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1451. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों में विभिन्न ग्रेडों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं आरक्षण का लाभ लिये बिना उनमें से कितने-कितने अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) आरक्षण लागू होने के बाद अन्य पिछड़े वर्ग के कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी 31 जुलाई, 1996 तक नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को छूट प्रदान कर उनके लिए आरक्षित पदों को न भरने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सभी आरक्षित पदों को पूरी तरह भरने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन): (क) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण प्रदान करने के निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करने को उच्च प्राथमिकता देने के अवलोकन में मंत्रालयों/विभागों पर इस बात के लिए जोर दिया गया था कि किसी वर्ष विशेष में अन्य पिछड़े वर्ग की भर्ती संबंधी आंकड़े वर्ष समाप्त होने के बाद तुरन्त उपलब्ध कराए जाएं। 65 मंत्रालयों/विभागों में से 24 से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 31.12.95 तक अन्य पिछड़े वर्गों के 7160 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है।

(ग) इस प्रकार का कोई दृष्टांत विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Loans for Private Power Producers

1452. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the response from the private power producers for the grant of loan is very poor and if so, the reasons therefor;

(b) the number of firms who have so far submitted their applications for loans and how many of them have since been cleared alongwith the details thereof; and

(c) by when the remaining applications are proposed to be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND